बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 161 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

जनकपुरी गड्ढा केस- 877 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश, तीन आरोपियों के नाम शामिल

नई दिल्ली । दिल्ली के जनकपुरी गड्ढा केस में तीन आरोपियों के खिलाफ सात अप्रैल को न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया गया है। यह आरोपपत्र कुल 877 पृष्ठों का है। आरोपियों में मुख्य ठेकेदार कंपनी केकेस्पन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के निलंबित निदेशक हिमांशु गुप्ता शामिल हैं। उनकी आयु 45 वर्ष है। दूसरे आरोपी राजेश कुमार हैं, जो उक्त परियोजना के उप-ठेकेदार हैं। राजेश कुमार की आयु 47 वर्ष है। तीसरा आरोपी योगेश है, जिसकी आयु 23 वर्ष है। योगेश को आरोपी राजेश कुमार ने परियोजना में मजदूर के तौर पर तैनात किया था। अन्य आरोपितों और संदिग्धों के संबंध में जांच अभी जारी है।

काँप33 में नई आम सहमति बनाने का दबाव पड़ता, इसलिए मेजबानी से अलग हुई सरकार - कांग्रेस

नई दिल्ली ।

कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि सरकार ने वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP33) की मेजबानी नहीं करने का फैसला किया क्योंकि इस सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत पर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक नई आम सहमति बनाने के लिए अधिक दबाव पड़ सकता था, जिसमें भविष्य के लिए लक्ष्यों को बढ़ाना भी शामिल होता। भारत ने वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सीओपी33 की मेजबानी करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2023 में दुबई में आयोजित सीओपी28 के दौरान भारत को सीओपी33 के मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया था। आम तौर पर किसी भी सीओपी सम्मेलन का आयोजन स्थल दो वर्ष पहले तय किया जाता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के दो बयानों के वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, एक दिसंबर 2023 को, प्रधानमंत्री ने दुबई में बड़ी घोषणा की थी कि भारत 2028 के अंत में भारत में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। स्पष्ट रूप से उनका इरादा 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले के महीनों में इस वैश्विक सभा का लाभ उठाने का था, जैसा कि नरेन्द्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नई दिल्ली में जी 20 शिखर सम्मेलन आयोजित करके किया था। उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित रूप से बुधवार रात यह घोषणा की गई कि भारत सीओपी 2028 सम्मेलन की मेजबानी नहीं करेगा। रमेश ने दावा किया, अचानक लिए गए इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया गया है। लेकिन यह लघु और मध्यम अवधि में कार्बन उत्सर्जन संबंधी अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की मोदी सरकार की सच्ची प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। 2028 तक, आईपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति) की सातवीं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित हो सकती है और यह 2028 सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत पर एक नई आम सहमति बनाने के लिए अधिक दबाव डाल सकती थी जिसमें निस्संदेह, भविष्य के लिए महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना शामिल होगा। रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्या हमें याद है कि प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले जलवायु परिवर्तन के बारे में अपने दृष्टिकोण पर बच्चों के एक समूह से क्या कहा था? उन्होंने टिप्पणी की थी कि लोग बदल गए हैं, जलवायु नहीं। अजीबोगरीब बात है।

दिल्ली विधानसभा सुरक्षा मामला- सरबजीत को लेकर आज पंजाब जाएगी दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली ।

दिल्ली विधानसभा में वीवीआईपी गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए पीलीभीत निवासी सरबजीत सिंह से दिल्ली पुलिस की कई टीमें पूछताछ कर रही हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी टीम को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि पुलिस के कुछ अधिकारी उसकी दी गई जानकारी को डायरी कर रहे हैं। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि बृहस्पतिवार को एक टीम सरबजीत को लेकर पंजाब जाएगी। पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आनंदपुर साहिब पहुंचने के बाद आरोपी किस-किस से मिला। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि गिरफ्तारी के समय टीम को सरबजीत का फोन नहीं मिला है। उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मोबाइल फोन करनाल में अमन ढाबे के पास खो गया था। पुलिस की एक टीम बुधवार को सरबजीत के मोबाइल की तलाश में गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सीडीआर की पड़ताल में पता चला है कि पंजाब से लौटते समय अंबाला में उसका मोबाइल फोन बंद हो गया था। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या वाकई में गलती से फोन खो गया या जानबूझकर सूचनाएं छिपाने के लिए उसने मोबाइल को गायब कर दिया है। पुलिस टीम सरबजीत का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए टेरर एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। उत्तरी जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सरबजीत के साथ पकड़े गए दोनों टैक्सी चालक नरेश, हरीश को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। छानबीन में पता चला है कि आरोपी ने रास्ता न पता होने की बात कर दोनों को गुमराह कर अपने साथ गाड़ी में बैठाया था। मामले की छानबीन कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी सरबजीत के पुराने रिकॉर्ड और किसान आंदोलन में उसकी सक्रियता को देखते हुए पुलिस की टीम टेरर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। उसके पिछले कुछ साल के बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है। इस बात का पता करने का प्रयास किया जा रहा है बैंक खाते में पैसे कहां से आए। सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल कर इस बात का भी पता किया जा रहा है कि आरोपी किन-किन लोगों के संपर्क में था। उसकी लगातार किन लोगों से बातचीत होती थी। इसके लिए टीम पीलीभीत जाकर भी उसके परिजनों व बाकी लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है।

तटीय राज्यों ने चुनौती को अवसर में बदला, ओम बिरला बोले- विकसित भारत में विधायिकाओं की अहम भूमिका

नई दिल्ली ।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि तटीय राज्यों ने अपनी चुनौतियों को अवसर में बदलकर विकास का नया मॉडल पेश किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इसी दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक लागू किया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन-VII सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जैसे तटीय राज्यों के सामने प्राकृतिक और भौगोलिक चुनौतियां रही हैं, लेकिन उनके नेतृत्व ने इन्हें विकास के अवसर में बदला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने लंबे कार्यकाल में सूखा, लंबी तटीय सीमा और जनजातीय क्षेत्रों जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए औद्योगिकीकरण, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा दिया। नर्मदा का पानी सूखे इलाकों तक पहुंचाया गया और वैश्विक बदलावों के अनुरूप नई तकनीकों को अपनाया गया। बिरला ने कहा कि अन्य तटीय राज्यों ने भी संकट और आपदाओं से निपटने के लिए कानून और नीतियां बनाईं, जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी विकास सुनिश्चित हुआ। दें हैं उन्होंने कहा कि जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से काफी उम्मीदें हैं और गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा को आपस में बेहतर नीतियों और अनुभवों का आदान-प्रदान करना चाहिए। उन्होंने राज्यों की विधानसभाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जरूरत पर भी जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया भारत की संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ मानती है और 1952 से हर चुनाव में बढ़ती मतदाता भागीदारी इसकी सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आज का दौर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, लेकिन इसके साथ मानवीय संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। बेहतर नीति और कानून पर सार्थक चर्चा करने वाले विधायक ही अपने राज्यों में प्रभावशाली नेता बनते हैं। बिरला ने यह भी कहा कि देश के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जैसे तटीय राज्यों का है। इस सम्मेलन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, गोवा और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष गणेश गाओंकर और राहुल नार्वेकर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने से हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा को आज बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद राजधानी में हड़कंप मच गया। इस धमकी के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विधानसभा परिसर, सचिवालय, कई स्कूलों और एक मेट्रो स्टेशन पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभ्यास शुरू कर दिया है। यह धमकी भरा ईमेल गुरुवार सुबह 8 बजकर 14 मिनट पर विधानसभा से जुड़े कई सरकारी और अन्य इनबॉक्स में पहुंचा। ईमेल में दिन के विभिन्न समयों पर विधानसभा, सचिवालय, कुछ स्कूलों और एक मेट्रो स्टेशन पर संभावित विस्फोटों की चेतावनी दी गई थी । सूचना मिलते ही, दिल्ली पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की टीमों के साथ मिलकर विधानसभा परिसर, सचिवालय, लक्षित स्कूलों और मेट्रो स्टेशनों पर व्यापक एंटी-सबोटेज जांच शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों द्वारा चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। इस घटना के बाद, दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दिल्ली विधानसभा को मिली बम की धमकी ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और तत्परता को उजागर किया है। हालांकि, इस तरह की धमकियों से आम जनजीवन में भय का माहौल उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में, सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के साथ-साथ, ऐसी धमकियों के स्रोत का पता लगाना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नया आधार कार्ड छह साल तक के बच्चों को ही मिले; अदालत में पीआईएल दाखिल कर नियम सख्त करने की अपील

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि नया आधार कार्ड जारी करने की उम्र सीमा तय की जाए। याचिका के अनुसार, नया आधार केवल 6 साल तक के बच्चों को ही मिलना चाहिए। वयस्कों और किशोरों के लिए आधार बनवाने के नियम बहुत कड़े होने चाहिए। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था का फायदा उठाकर घुसपैठिये आसानी से आधार कार्ड बनवा रहे हैं। इसके बाद वे खुद को भारतीय नागरिक बताने लगते हैं। इससे देश की सुरक्षा, सरकारी संसाधनों और चुनाव प्रक्रिया को खतरा पैदा हो रहा है।याचिका में मांग की गई है कि आधार केंद्रों पर बड़े बोर्ड लगाए जाएं। इन पर साफ लिखा होना चाहिए कि आधार कार्ड केवल पहचान का सबूत है, यह नागरिकता, पते या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर कोई वयस्क आधार बनवाना चाहता है, तो उसका वेरिफिकेशन एसडीएम या तहसीलदार जैसे बड़े अधिकारियों से होना चाहिए। याचिका के अनुसार,

देश में अब तक 144 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड बन चुके हैं। इसलिए नए नियमों से असली नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा।

याचिका में यह भी कहा गया है कि फर्जी दस्तावेजों से आधार बनवाने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। घुसपैठिये आधार के जरिए राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे अन्य दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट आज कई जरूरी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इनमें जनता से जुड़े कई संवेदनशील मामले शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। यह मांग पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने के मामले में की गई है। इसके अलावा, भीमा कोरेगांव मामले में कार्यकर्ता ज्योति जगताप की अर्जी पर भी सुनवाई होगी। इसके साथ ही, तमिलनाडु और केरल के बीच मुल्लापेरियार बांध की मरम्मत के विवाद पर भी कोर्ट विचार करेगा। सड़क सुरक्षा और हाईवे से अतिक्रमण हटाने से जुड़ी याचिका पर भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट इन सभी मामलों पर जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा।

नारी शक्ति को सशक्त करें

21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है जब समानता, समावेशन और जनभागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी। यह ऐसा समय है जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है जो हमारे लोकतंत्र को अधिक व्यापक एवं और अधिक प्रतिनिधिक बनाए। संसद का यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभा संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। यह क्षण इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है जब देश का वातावरण उत्सव, नवीनता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में भारत के अलग-अलग हिस्सों में अनेक पर्व मनाए जाएंगे। असम के लोग रोंगाली बिहू मनाने वाले हैं और ओडिशा में महा विषुब पणा संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी। केरलम में विषु पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सुकता से पुथांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को बैसाखी के पर्व का इंतजार है। हमारे ये पावन पर्व हर किसी में एक नई आशा का संचार करने वाले हैं। भारत के साथ-साथ दुनियाभर में इन त्यौहारों को मनाने वाले सभी लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये कामना करता हूं कि ये दिव्य और पावन अवसर हम सभी के जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आएं। इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं, जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की है। इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच, 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी नारीशक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारीशक्ति मिसाल बन रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, खेल के मैदान से लेकर सशस्त्र बलों तक और संगीत से लेकर कला के क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं-बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है जब माताओं-बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद भी राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। इस कमी को अब दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है। इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में सुधार भी होता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार-बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके। फिर भी, इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है। अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर हमारे संविधान की मूल भावना के साथ गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां समानता न केवल संविधान में निहित हो, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाए। विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राष्ट्र का भविष्य तय करने में प्रत्येक नागरिक की समान भूमिका हो। अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। दशकों से इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। इस पर चर्चा हुई है, इसे बार-बार दोहराया गया है। अगर अब भी हम इसे आगे टालते हैं तो उसका अर्थ यही होगा कि हम उस असंतुलन को और लंबा खींच रहे हैं, जिसे हम पहचानते भी हैं और सुधारने की क्षमता भी रखते हैं। आज भारत पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारी संस्थाएं सभी नागरिकों, विशेष रूप से हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करें। इससे न सिर्फ दशकों पुराना संकल्प पूरा होगा, बल्कि विकास की गति को बनाए रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। यह हमारे लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने और भविष्य के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह समय सामूहिक संकल्प का है। यह किसी एक सरकार, एक दल या एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का विषय है। हमें मिलकर इस कदम के महत्व को समझना है और मिलकर ही इसे साकार करना है। यही हमारी नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व भी है, इसलिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ फैसले अपने समय से बड़े होते हैं।

युद्ध से शांति की ओर

40 दिन के जबरदस्त घमासान के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान ने 15 दिन के युद्ध विराम पर सहमति की खबर ने समूचे विश्व को राहत की सांस दी है। 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को पाषाण युग में भेजने, कुछ घंटों में उसकी सभ्यता खत्म करने की धमकियां दे रहे थे, ने नाटकीय घटनाक्रम के बीच स्वयं युद्ध विराम पर सहमति का ऐलान किया। ईरान ने भी इस पर अपनी सहमति जताई और इजराइल ने भी इसे स्वीकार किया। डोनाल्ड ट्रम्प ने स्वीकार किया कि यद्यपि पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई लेकिन चीन ने ईरान को युद्ध विराम के लिए राजी किया। युद्धों को समाप्त करने की व्यवस्था में युद्ध विरामों का स्थान हमेशा से ही केन्द्रीय रहा है। बड़े-बड़े युद्ध अंततः मेज पर ही आकर खत्म होते हैं। युद्ध विराम का उद्देश्य संवाद स्थापित करना, मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना और किसी समाधान तक पहुंचने के लिए समझौता करना होता है। युद्ध विराम को कूटनीति के अनिवार्य साधन के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के बिना युद्ध प्रारंभ नहीं होते लेकिन आज के दौर में डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। युद्ध विराम भी विश्वासघातों के बीच रणनीतिक हथियार बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा युद्ध विराम की घोषणा एक रणनीतिक मजबूरी के रूप में देखा जा रहा है। ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद किए जाने के वैश्विक तेल आपूर्ति खतरे में पड़ चुकी थी जिससे तेल की कीमतें बढ़ गईं थीं और हाहाकार मच गया था। आपूर्ति बाधित होने से गैस की कीमतों में भी उछाल आ चुका था। नाटो और अमेरिका के मित्र यूरोपीय देश इस कोहराम के लिए ट्रम्प को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और उन्होंने भी युद्ध से किनारा कर लिया था। अमेरिका को इस युद्ध में कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा उसे अपने बेशकीमती लड़ाकू विमान और हैलीकॉप्टर खोने पड़े। 40 दिन के युद्ध में उसे अरबों रुपए खर्च करने पड़े। लगातार हमलों के बावजूद ईरान की प्रतिरोधक क्षमता और इजराइल-अमेरिका के खिलाफ जवाबी हमले की क्षमता ने ट्रम्प प्रशासन को युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया। ईरान ने अपने ड्रोनों और मिसाइलों के हमलों से अमेरिका और इजराइल को ऐसा झटका दिया जिसकी कल्पना कभी वैश्विक शक्ति माने गए अमेरिका ने भी नहीं की होगी। अमेरिका के भीतर भी युद्ध के विरोध में जनभावनाएं उभार ले चुकी थी और ट्रम्प की लोकप्रियता जमीन सूंघने लगी थी। ट्रम्प पर न केवल खाड़ी देशों, मित्र देशों का बल्कि देश के भीतर से भी काफी दबाव था कि युद्ध को किसी न किसी हालत में रोका जाए। यद्यपि ट्रम्प ने ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर बहुत कड़ी शर्तें रखी थीं, जिसे वे अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहे थे लेकिन उनकी धमकियां युद्ध विराम समझौते के लिए दबाव डालने की रणनीति ही थी। पाकिस्तान भले ही मध्यस्थता के लिए अपनी पीठ ठोके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष मुल्ला मुनीर कुछ भी बयानबाजी करें। यह साफ है कि पाकिस्तान की भूमिका एक संदेशवाहक के रूप में ही थी। उन्होंने केवल ईरान की शर्तों और अमेरिका की शर्तों के प्रस्तावों का आदान-प्रदान ही करवाया। चीन ने ईरान को समझौते के लिए राजी किया। ईरान की सड़कों पर जश्न का माहौल है। तेहरान के लोग अपने देश का झंडा लेकर सड़कों पर लहरा रहे हैं। ईरान की सरकार युद्ध विराम समझौते को अपनी जीत के रूप में पेश कर रही है। ईरान ने युद्ध की शुरुआत में अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और आईआरजीसी के वरिष्ठ जनरलों को हमलों में खोया था और यह लड़ाई वहां के शासन के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। ईरान युद्ध को विजयी इसलिए मान रहा है क्योंकि वह अमेरिका और इजराइल से टक्कर लेकर 40 दिन तक युद्ध में टिका रहा। यह जीत तेहरान की राष्ट्रवादी जनता की भी मानी जा रही है। ईरान की जनता ने एक मंत्री के आह्वान पर जिस तरह से पावर प्लांटों के चारों तरफ मानव शृंखला बनाकर खुद को ढाल के रूप में प्रस्तुत किया वह अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। यह वही जनता है जो धार्मिक सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी लेकिन अमेरिका-इजराइल के हमलों ने ईरानी अवाम को एकजुट कर दिया। ईरान ने 10 शर्तें रखी हैं, जिसमें हमले तुरन्त रोकने, उस पर प्रतिबंध हटाने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव रद्द करने और संवर्धित यूरेनियम उसके पास सुरक्षित रहने इत्यादि शामिल हैं। सबसे बड़ा मसला होर्मुज स्ट्रेट को खोलने का था जिसके लिए ईरान तैयार है लेकिन उसकी शर्त यह है कि दो हफ्ते तक वह होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों से टोल टैक्स वसूलेगा ताकि उसके नुकसान की भरपाई हो सके। अब इन शर्तों पर पाकिस्तान में बातचीत होगी। अमेरिका ने भी ईरान के सामने 15 शर्तें रखी हैं। अब यह जरूरी है कि अमेरिका और ईरान में बातचीत को लेकर भरोसा कायम हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि बातचीत काफी सख्त रहेगी। कुल मिलाकर युद्ध विराम समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ दिखाई देता है। युद्ध खत्म होना और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ना दुनिया के लिए अच्छा है लेकिन इससे वर्ल्ड आर्डर बदल जाएगा। अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी देशों को इस बात का अहसास हो चुका है कि सुरक्षा की दृष्टि से वे ईरान के मुकाबले बहुत कमजोर हैं और अमेरिका उनकी रक्षा करने में नाकाम रहा है।

सम्पादकीय...

भारत को विश्वगुरु बनाना ही आर.एस.एस. का उद्देश्य

'शाखा' जैसी अद्वितीय प्रणाली के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण का कार्य संघ करता है। इसी से लाखों स्वयंसेवक तैयार हुए हैं, जिनके जीवन के आदर्श व्यवहार से समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखता है। संघ की कार्यपद्धति अन्य संगठनों से भिन्न और विशिष्ट है। बाल स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक, सभी एक ही आदेश पर कार्य करते हैं। शाखा में होने वाले छोटे-छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से अनुशासन और संस्कार विकसित होते हैं। संघ के साथ ही समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वयंसेवकों ने 40 से अधिक संगठनों, जैसे ए.बी.वी.पी., लघु उद्योग भारती, सेवा भारती, विद्या भारती की स्थापना की, जो अपने-अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये सभी स्वतंत्र, स्वायत्त और स्वावलंबी संगठन हैं। भारत को पुन: 'विश्वगुरु' के स्थान पर प्रतिष्ठित कर भारत माता को परम वैभव पर ले जाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। आर.एस.एस. के पहले चार प्रचारक – 1925 में संगठन के रूप में आकार लेने पर आर.एस.एस. के आद्य सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार के सामने चुनौती थी कि संघ के विचारों का देशभर में प्रचार-प्रसार कैसे किया जाए। उन्हें समर्पित, पूर्णकालिक और संघ की भावना में दीक्षित कार्यकर्ताओं की तलाश थी। प्राचीन समय में जैसे ऋषि-महर्षि परम्परा थी, जो जीवन प्रणाली का अध्ययन कर अलग-अलग समय पर मनुष्य जीवन में आने वाली समस्या का हल प्राणी मात्र को देते थे, उसी प्रकार प्रचारक भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने में मार्गदर्शन करते हैं। इस परम्परा में पहले 4 प्रचारक थे बाबा साहब आपटे, दादा राव परमार्थ, रामभाऊ जामगडे और गोपाल राव येरकुंटवार। 2 वर्ष तक प्रशिक्षण के बाद 1929 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने प्रचारक व्यवस्था को औपचारिक रूप देने की शुरूआत की। 1930 में जब डॉ. हेडगेवार सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जंगल सत्याग्रह में भाग लेने पहुंचे तो सरसंघचालक के पद से इस्तीफा दिया। डॉ. परांजपे को नया सरसंघचालक बनाया गया। डॉ. हेडगेवार को पता था कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। 1931 में बाबा साहब आपटे को डॉ. हेडगेवार ने जेल से बाहर आने के बाद पूर्णकालिक प्रचारक बनाने के लिए चुना। इस तरह इन चारों को संघ की पहली प्रचारक टोली के तौर पर जाना जाता है। इनमें बाबा साहब आपटे को प्रथम प्रचारक माना जाता है। संघ के पहले पूर्णकालिक प्रचारकों की दीक्षा के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम नागपुर में रखा गया, जहां प्रमुख स्वयंसेवक उपस्थित थे। उसी कार्यक्रम में डॉ. हेडगेवार का छोटा सा सम्बोधन हुआ, जिसमें संगठन का संकल्प और प्रचारकों का जीवन साधुओं की तरह होना चाहिए, इसी पर उनका जोर था। उसके बाद उनके केन्द्र बताए गए कि उनको प्रचार के लिए किस शहर या प्रांत में जाना है। उत्तर-पूर्व में 'संघ के बीज' बोने वाले पहले प्रचारक दादाराव परमार्थ यानी गोविंद सीताराम परमार्थ नागपुर के रहने वाले थे। 10वीं की परीक्षा की उत्तरपुस्तिका में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली।

युद्धविराम का वैश्विक प्रभाव ऊर्जा,अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर असर होगा जो आम जनता के लिए राहत की बात

वैश्विक स्तरपर 8 अप्रैल 2026 को पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया,जब डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के साथ दो सप्ताह के अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की गई। यह घोषणा चेतावनी की समय सीमा समाप्त होने के 90 मिनटपूर्व उस समय आई जब सैन्य टकराव अपने चरम पर था और सभ्यता के अंत जैसी कठोर चेतावनियां दी जा चुकी थीं। यद्यपि इस कदम से वैश्विक स्तरपर राहत की सांस ली गई,परंतु युद्धविराम के कुछ ही घंटों बाद ईरान की ऑयल रिफाइनरी में धमाका और खाड़ी देशों यूएई व कुवैत पर मिसाइल एवं ड्रोन हमले इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि यह शांति स्थायी नहीं बल्कि अत्यंत नाजुक है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह केवल दो देशों के बीच संघर्ष नहीं,बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन,और क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों का व्यापक प्रतिबिंबहै।अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह युद्धविराम मूलतः एक टैक्टिकल पॉज है, न कि स्थायी समाधान। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह युद्ध का अंत नहीं बल्कि वार्ता की संभावनाओं को खोलने के लिए लिया गया कदम है। ईरान ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी सैन्य गतिविधियां पूरी तरह बंद नहीं होंगी,बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पर हमले रुकते हैं या नहीं।इस प्रकार, यह युद्धविराम शर्तों पर आधारित है,एक ऐसा संतुलन जहां दोनों पक्ष अपनी सैन्य तैयारियों को बनाए रखते हुए कूटनीतिक संवाद का रास्ता तलाश रहे हैं। यही कारण है कि ईरान ने साफ कहा कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं, जो इस समझौते की अस्थिरता को उजागर करता है। साथियों बात अगर हम स्टेट ऑफ होर्मुज- वैश्विक ऊर्जा राजनीति का केंद्र इसको समझने की करें तो इस पूरे संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्टेट ऑफ होर्मुज है, जिससे होकर विश्व के लगभग 20 प्रतिशत तेल की आपूर्ति होती है। अमेरिका की प्रमुख मांग रही है कि इस जलमार्ग को तुरंत और सुरक्षित रूप से खोला जाए।ईरान ने इस पर सैद्धांतिक सहमति तो दी है,लेकिन अपनी शर्तों के साथ,जिसमें उसकी सैन्य निगरानी औरतकनीकी नियंत्रण शामिल है। यह दर्शाता है कि ईरान इस जलमार्ग को केवल व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार के रूप में देखता है।यदि होर्मुज बंद होता है, तो वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल, सप्लाई चेन बाधित होना, और आर्थिक अस्थिरता निश्चित है। इसीलिए इस जलमार्ग का खुलना पूरी दुनिया के लिए राहत का संकेत माना जा रहा है। साथियों बात अगर हम ईरान की 10 शर्तें- शांति यारणनीतिक दबाव? इसको समझने की करें तो ईरान ने युद्धविराम को स्थायी शांति में बदलने के लिए 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है,जो केवल सैन्य संघर्ष समाप्त करने तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक भू-राजनीतिक पुनर्संतुलन की मांग करता है।इन शर्तों में अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना, जब्त संपत्तियों की वापसी, पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, और क्षेत्रीय संघर्षों जैसे यमन, लेबनान, इराक–का स्थायी समाधान शामिल है। साथ ही, ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई है, लेकिन इसके साथ यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की बात भी रखी है।यहीं सबसे बड़ा विवाद उत्पन्न होता है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है।

फारसी और अंग्रेजी दस्तावेजों में यूरेनियम संवर्धन को लेकर अंतर इस वार्ता को और जटिल बनाता है। साथियों बात अगर हम जमीनी हकीकत- युद्धविराम के बावजूद जारी हमले इसको समझने की करें तोयुद्धविराम की घोषणा के बावजूद, खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं। इजराइल द्वारा ईरान पर हमले जारी रखना और ईरान की ओर सेजवाबी कार्रवाई इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तरपर स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है।यह विरोधाभास राजनीतिक घोषणाएं बनाम वास्तविक घटनाएं इस संघर्ष की जटिलता को उजागर करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल दो देशों तक सीमित नहीं बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष बन चुका है, जिसमें कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खिलाड़ीरणनीतिक रूप से शामिल है। साथियों बात अगर हम इस संपूर्ण मामले पर भारत की प्रतिक्रिया संतुलित कूटनीति और मानवीय चिंता को समझने की करें तो,भारत ने इस युद्धविराम का स्वागत करते हुए इसे शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से संवाद और कूटनीति का समर्थक रहा है।हालांकि, भारत की प्राथमिक चिंता अपने नागरिकों की सुरक्षा है। 8 अप्रैल 2026 को एम्बेसी ऑफ़ इंडिया इन तेहरान ने एक आपातकालीन एडवाइजरी जारी कर ईरान में रह रहे लगभग 9,000 भारतीयों से देश छोड़ने की अपील की।यह कदम दर्शाता है कि भारत स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है और किसी भी संभावित खतरे से पहले अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना चाहता है। यह प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का उदाहरण है। साथियों बात अगर हम सीजफायर के मुद्दे पर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया- कूटनीति बनाम राजनीति को समझने की करें तो इस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव भारत की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ा है। महाराष्ट्र क्षेत्रीय पार्टी के एक नेता ने केंद्र सरकार और पीएम पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारत इस वैश्विक संकट में प्रभावी भूमिका निभाने में असफल रहा।उन्होंने पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता का हवाला देते हुए सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए।

इसके जवाब में सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्थिति की गंभीरता को समझना आवश्यक है और भारत अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य कर रहा है।यह बहस दर्शाती है कि विदेश नीति भी अब घरेलू राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। साथियों बात कर हम सीजफायर के इस मुद्दे पर पाकिस्तान की भूमिका- कूटनीतिक अवसर या अतिशयोक्ति? इसको समझने की करें तो इस युद्धविराम में पाकिस्तानी पीएम और सेना प्रमुख की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है। ट्रंप ने स्वयं दावा किया कि पाकिस्तान के अनुरोध पर उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोकी फिर भी हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि सीमित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान इस स्थिति को एक कूटनीतिक अवसर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। इससे दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में भी नए समीकरण बन सकते हैं।इसी बीच, भारत द्वारा पाकिस्तान सीमा के पास नोटम जारी करना और बंगाल की खाड़ी में जीएनएसएस (जीपीएस) जैमिंग ट्रायल की योजना इस बात का संकेत है कि आधुनिक युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहा।सैटेलाइट सिग्नल को बाधित करने की क्षमता भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यह कदम भारत की तकनीकी और सामरिक तैयारी को दर्शाता है, जो बदलते वैश्विक सुरक्षा वातावरण के अनुरूप है। साथियों बात अगर हम इस पूरे मामले और सीज फायर को अंतरराष्ट्रीय परिपेक्ष में समझने की करें तो वैश्विक प्रभाव- ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर असर होगा इस संघर्ष का प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्ग, और वित्तीय बाजार–आल इंटरकनेक्टेड हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने या बंद होने का सीधा असर तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके अलावा, यह संघर्ष अमेरिका, ईरान, इजरायल, खाड़ी देशों और अन्य शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करता है। यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है, तो इसका असर वैश्विक मंदी तक पहुंच सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अनिश्चित शांति और लंबी कूटनीतिक यात्रा 8 अप्रैल 2026 का यह युद्धविराम एक राहत अवश्य प्रदान करता है, लेकिन यह स्थायी शांति का संकेत नहीं है।

ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास, परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद, और क्षेत्रीय संघर्षों की जटिलता इस समझौते को बेहद नाजुक बनाती है।भारत जैसे देशों के लिए यह समय संतुलित कूटनीति, नागरिक सुरक्षा, और रणनीतिक तैयारी का है। वहीं, वैश्विक समुदाय के लिए यह एक चेतावनी है कि केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि संवाद, सहयोग और समझ से ही स्थायी शांति संभव है।इस प्रकार, यह युद्धविराम एक अंत नहीं बल्कि एक अंतराल है एक ऐसा अंतराल, जिसमें दुनिया को यह तय करना है कि वह संघर्ष की ओर बढ़ेगी या सहयोग की ओर बढ़ेगी।

कहां गए शांति के कपोत उड़ाने वाले?

आज की दुनिया बारूद से धधक रही है। रूस-यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक, हर तरफ मिसाइलों की गूँज है। शांति की बातें अब सुनाई नहीं देतीं। शांति के कपोत उड़ाने वाले दिखाई देने बंद हो गए। युद्ध की विभीषिका के विरोध में प्रदर्शन करने और मोमबत्ती जलाने वाले अब सड़कों से गायब हैं। युद्ध के विरोध के स्वर धीमे ही नहीं हुए, पूरी तरह खामोश हो गए। युद्ध के संदेश अब किताबों में ही बंद होकर रह गए हैं। युद्धों के विरोध की कहीं से बात नहीं उठ रही। दुनिया में शांति स्थित करने के लिए बने संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुंह पर टेप चिपक गया। वह देख सकता है। न कुछ बोल सकता है। न आदेश कर सकता है। विडंबना देखिए कि इक्कीसवीं सदी में हम मंगल पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन के चंद टुकड़ों और आपसी वर्चस्व के लिए हजारों बेगुनाहों का खून बहाने से भी पीछे नहीं हट रहे। युद्ध चाहे रूस और यूक्रेन के बीच हो, या इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव हो। जीत के झंडे चाहे जिस देश के हाथ आएं, हारती हमेशा मानवता है। इन युद्ध में विजयी कोई भी हो, सदा पराजित तो मानव होती है। मरती बस इंसानियत है। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समस्या का समाधान नहीं रहा, बल्कि यह नई समस्याओं का जन्मदाता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बार कहा कि दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। कई मंचों से उन्होंने यह मांग उठाई, किंतु किसी भी देश ने शांति का समर्थन नहीं किया। सब देश गूंगे बन कर रह गए। आज भी ये ही हाल है। गरता ईरान खाड़ी के उन देशों पर मिसाइल और ड्रोन दाग कर तबाही मचा रहा है, जिनमें अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। अपनी बर्बादी होते देख ये देश ईरान पर अमेरिकी हमलों का उस तरह विरोध नहीं कर रहे, जिस तरह कि करना चाहिए। रूस-यूक्रेन युद्ध के समय जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट को जन्म दिया तो मध्य पूर्व (इजराइल-हमास-ईरान) के संघर्ष ने दुनिया को धार्मिक और कूटनीतिक ध्रुवीकरण के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इन लड़ाइयों में टैंकों की गड़गड़ाहट के बीच जो आवाज दब जाती है, वह है–एक मासूम बच्चे की चीख और एक बेबस माँ की कराह। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत वे लोग चुकाते हैं जिनका राजनीति या सत्ता की लालसा से कोई लेना-देना नहीं होता। यूक्रेन के कीव से लेकर गाजा की गलियों और ईरान के गांव तक तक, हजारों औरतें और बच्चे मौत की नींद सो चुके हैं। जो उम्र खिलौनों से खेलने की थी, उस उम्र में बच्चे बमों के धमाकों को पहचानना सीख रहे हैं। हजारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं और लाखों का भविष्य मलबे के नीचे दब गया है। युद्ध के दौरान महिलाओं को न केवल विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है, बल्कि वे शारीरिक और मानसिक हिंसा का सबसे आसान लक्ष्य बनती है। युद्ध केवल इंसान को नहीं मारता, वह सदियों से बनी-बनाई सभ्यताओं और बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर देता है। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर गिरते बम यह दर्शाते हैं कि आधुनिक समाज कितना -असंवेदनशील- हो चुका है। जब एक अस्पताल पर मिसाइल गिरती है, तो वह केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं ढहती, बल्कि इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इन लड़ाइयों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया भर में अनाज की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ दिया। इससे गरीब देशों में भुखमरी का खतरा बढ़ गया। ईंधन की बढ़ती कीमतों और खाद्य पदार्थों की कमी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जो खरबों डॉलर शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में खर्च होने चाहिए थे, वे आज आधुनिक हथियार और मिसाइलें बनाने में झोंके जा रहे हैं। युद्ध का एक और खामोश शिकार हमारा पर्यावरण है। हजारों टन गोला-बारूद का इस्तेमाल वायुमंडल को जहरीला बना रहा है। जंगलों की आग, समुद्री प्रदूषण और जमीन में धंसे बारूदी सुरंग आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मौत का जाल बिछा रहे हैं। हम जिस धरती को बचाने की कसमें खाते हैं, उसी को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। संसाधनों को बरबाद कर रहे हैं। जब हम टीवी पर बमबारी के दृश्य देखते हैं और उन्हें केवल एक -न्यूज अपडेट- की तरह छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे भीतर की इंसानियत मर चुकी है। युद्ध हमें क्रूर बना देता है। हम मौतों को केवल %आंकड़ों% में गिनने लगते हैं। घृणा का यह बीज जो आज बोया जा रहा है, वह भविष्य में और अधिक कट्टरपंथ और आतंकवाद को जन्म देगा। अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बन गया है। उसने इराक पर यह कह कर हमला किया था कि उसके पास कैमिकल और अन्य घातक शस्त्र हैं। इराक हार गया। सद्दाम हुसैन पकड़े ही नहीं गए, उन्हें फांसी हो गई, किंतु अमेरिका इराक से कुछ भी बरामद नहीं कर पाया। उसका सब झूंठा प्रचार रहा। अब ईरान पर यह कह कर इजरायल और अमेरिका ने हमला किया कि वह परमाणु बम बनाने के नजदीक है।

उसकी इस शक्ति को खत्म करना है। हमले जारी हैं। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए अपने मन की बात कह दी कि उसे ईरान के तेल पर कब्जा करना है। तीन जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके देश (काराकस) से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नार्को-आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों के बाद की गई। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। बहाना मादक पदार्थों की तस्करी रोकना था किंतु अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल वे बेचेंगे। उनकी मर्जी से बिकेगा। इस सब का मतलब साफ है कि दुनिया के संसाधनों पर अमेरिका की नजर है। वह किसी न किसी बहाने उन पर कब्जा करना चाहता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि अगर थोड़ा और समय मिला तो अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल सकता है और वहां से तेल लेकर बड़ा मुनाफा कमा सकता है। उनके इस बयान ने पहले से चल रहे संघर्ष को और संवेदनशील बना दिया है। फिलहाल ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है। इस कारण दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतों में तेजी देखी जा रही।यह संघर्ष अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान और लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी कई खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हाल के दिनों में हमलों की संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन पूरी तरह रुकी नहीं है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने से इन्कार करने वाले ब्रिटेन जैसे वह देश होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने की वजह से जेट ईंधन नहीं पा रहे हैं। उनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सुझाव है- पहला- अमेरिका से तेल खरीदो, हमारे पास बहुत है। दूसरा- हिम्मत जुटाओ, जलडमरूमध्य पर जाओ और उसे अपने कब्जे में ले लो। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के पूर्व महानिदेशक मोहम्मद अल बारदेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी करने के बाद खाड़ी देशों से हस्तक्षेप करने की तत्काल अपील की है। पूर्व आईएईए प्रमुख ने विनाशकारी सैन्य टकराव की संभावना का जिक्र किया। बारदेई ने एक्स पर एक पोस्ट में पड़ोसी खाड़ी देशों को संबोधित करते हुए कहा, कृपया, एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दें, इससे पहले कि यह पागल शख्स इलाके को आग का गोला बना दे। मोहम्मद अल बारदेई ने अपनी गुहार को वैश्विक मंच तक पहुंचाते हुए युद्ध को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। संयुक्त राष्ट्र के साथ रूस-चीन-फ्रांस को संबोधित एक अलग पोस्ट में उन्होंने पूछा कि क्या इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है? युद्ध किसी समस्या का स्थायी हल नहीं है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/38862)

नदी में डूबने से किशोर की मौत, गांव में मातम

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। खड्डा थाना क्षेत्र के भैंसह्न गांव स्थित कोटवा टोला में बुधवार शाम एक दर्दनाक ह्रदसे में 16 वर्षीय किशोर की डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान संतराज (16) पुत्र लौकु राजभर के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, संतराज शाम को शौच के लिए गांव के पास नदी किनारे गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। आसपास कोई मौजूद न होने के कारण समय पर उसे बचाया नहीं जा सका। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में ग्रामीणों से जानकारी मिलने पर परिजन और गांव के लोग नदी किनारे पहुंचे और खोजबीन शुरू की। कुछ समय बाद उसका शव नदी से बरामद हुआ। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्कहा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संतराज दो भाइयों में सबसे छोटा था। पिता गांव में चाय की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी किनारे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पूरे गांव में शोक का माहौल है।

स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली व पुस्तक वितरण

पड़रौना,कुशीनगर।

नगर के जूनियर हाई स्कूल में स्कूल चलो अभियान÷ के अंतर्गत प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा बच्चों को निशुल्क पुस्तकें वितरित कीं। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति और समाज के विकास का आधार है। उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम के अंतर्गत बिना जायसवाल एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. रामजीयावन मौर्य,नें जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में छात्रों ने सब पढ़ें, सब बढ़ें÷ जैसे नारों के माध्यम से शिक्षा के प्रति संदेश दिया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र बहादुर सिंह, अमित चौहान, प्रधानाध्यापक बृंदा चौहान सहित शिक्षकगण, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन शिक्षा के प्रति जागरूकता के संकल्प के साथ हुआ।

कार सवारों ने नहर सड़क पर 8 राहगीरों को रौंदा, आधा दर्जन जिला अस्पताल रेफर

नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर। कार सवारों ने खड्डा थाना क्षेत्र के बंजारी पट्टी नहर पुल के समीप बड़ी नहर सड़क मार्ग पर राहगीरों सहित बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दिया, लगभग 200 मीटर तक सामने सड़क से आ रहे दर्जनों लोगों को गम्भीर रूप घायल कर एक बड़ा ह्रादसा कर दिया। एक के बाद एक ठोकर से घायल राहगीरों, सायकिल सवार सहित बाइक सवार इसके जद में आ गए। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सभी घायलों को तुर्कहा सीएचसी भर्ती कराया गया जहां 7 लोगों को चिकित्सकों ने गम्भीर स्थिति देख जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। पुलिस कार को कब्जे में लेकर आगे की। कार्रवाई में जुटी हुई है। बुधवार की शाम मुख्य पश्चिमी गंडक नहर सड़क मार्ग पर स्थित बंजारी पट्टी चौराहे के समीप कार सवारों ने एक भीषण हादसा कर दिया, सड़क मार्ग से पैदल, सायकिल व मोटरसाइकिल पर सवारों को बारी-बारी एक के बाद एक सामने पड़े लगभग 8 लोगो को भीषण टक्कर मार घायल कर दिया, जिसमें अमन यादव 14 वर्ष व राजू यादव निवासी खरट थाना निचलौल, खुशुबुद्दीन उम्र 54 वर्ष निवासी चरगहां थाना निचलौल, जोया उम्र 12 वर्ष, राधेश्याम उम्र 22 वर्ष व विशाल 30 वर्ष व रेतुल्ह 65 वर्ष व रामनरेश 72 वर्ष सभी निवासी गण बंजारी पट्टी थाना खड्डा ठोकर से घायल होकर सड़क पर गिरकर छटपटाने लगे।

महाप्रबंधक के भटनी आगमन पर एनई रेलवे मजदूर यूनियन ने सौंपा ज्ञापन, कर्मचारियों की समस्याएं उठाई

भटनी देवरिया।

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरणकर के भटनी आगमन पर एनई रेलवे मजदूर यूनियन भटनी इकाई द्वारा शाखा मंत्री मनोज सिंह के नेतृत्व में महर्षि देवरहा बाबा की फोटो एवं ज्ञापन सौंपकर उनका अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। इस दौरान यूनियन पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं से महाप्रबंधक को अवगत कराते हुए समाधान का निवेदन किया। प्रमुख मांगों में वाराणसी मंडल के पुराने जर्जर रेल आवासों को हटाकर नए मल्टी स्टोरी आवास बनवाने, गेटमैन कर्मचारियों की 12 घंटे ड्यूटी को घटाकर 8 घंटे करने, कर्मचारियों के प्रमोशन की व्यवस्था तथा इंटेक कोटे की अधिसूचना शीघ्र जारी करने की मांग शामिल रही। महाप्रबंधक ने सभी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने के दौरान शाखा मंत्री मनोज सिंह,अशोक गौतम,आलोक सिंह, गंगा प्रसाद पांडेय, मानसिंह यादव, पुष्पेंद्र कुमार, मुकेश मुर्मू,प्रशांत सिंह सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने भटनी जंक्शन का किया निरीक्षण, पुनर्विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश

भटनी देवरिया। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने गोरखपुर-मऊ रेलखण्ड के विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के दौरान भटनी जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन तथा मुख्यालय एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने भटनी जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटरों एवं अन्य यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के अंतर्गत चल रहे स्टेशन पुनर्विकास कार्यों का अवलोकन किया और कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की। महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भटनी जंक्शन पर चल रहे सभी पुनर्विकास कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण किए जाएं, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने स्टेशन परिसर की साफ-सफाई, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों ने महाप्रबंधक को चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी दी और स्टेशन के विकास से जुड़ी योजनाओं के बारे में अवगत कराया।

एनईआर रेलवे मेंस कांग्रेस के शाखा मंत्री अपनी मांगों को लेकर महाप्रबंधक से किया मौखिक आग्रह

भटनी देवरिया। दिन बृहस्पतिवार को पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक उदय बोरणकर के भटनी रेलवे स्टेशन आगमन पर पूर्वोत्तर रेलवे मेंस कांग्रेस के शाखा मंत्री उबैदुल्लह खान ने महाप्रबंधक से गेटमैन की ड्यूटी 12 घण्टे से 8 घण्टे की करने, रेलवे अस्पताल, मनोरंजन कक्ष, विद्युत को नगर पंचायत से अलग करने व 10फीसदी इंटेक कोटा वाराणसी डिवीजन से अलग करने का मौखिक आग्रह किया। इस दौरान सीनियर डीईएन कॉर्डिनेशन, सीनियर डीईएन फर्स्ट, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ आदि के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जांच में अंधेरगर्दी से उठा पर्दा तो उंगली दिखने लगा फैक्चर

महराजगंज।

कोठीभार थाना क्षेत्र के मुंडेरी चौबे गांव की फाबिया अंधेरगर्दी के खिलाफ हिम्मत नहीं हारीं। 3 जून 2025 को गांव में ही उनके साथ विरोधियों ने मारपीट की। कोठीभार थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद धारा में बढ़ोतरी के लिए टूटी हुई उंगली की जांच के लिए जिला अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने नो बोन फैक्चर की रिपोर्ट लगा दी। आरोप है कि डॉक्टरों ने रकम की मांग की, लेकिन फाबिया ने रकम नहीं दी तो रिपोर्ट गलत लगाकर दायित्व की इतिश्री कर किनारा कस लिया। फाबिया ने दूसरी बार जांच के लिए तत्कालीन सीएमओ से अनुरोध किया तो अंधेरगर्दी की कलई खुल गई। जांच रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने छोटी उंगली के मध्य पोर के शीर्ष का रेखीय विस्थापित फैक्चर बताया। जानकारी के अनुसार, 3 जून 2005 को मुंडेरी चौबे गांव की फाबिया के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इसमें फाबिया की उंगली फैक्चर हो गई थी। इसका डिजिटल एक्सरे बाहर से उसने कराया था। रिपोर्ट में साफ साफ उंगली में फैक्चर दिख रहा था, लेकिन जिला अस्पताल में एक्स रे के दौरान डॉक्टरों ने जांच रिपोर्ट में नो बोन फैक्चर की रिपोर्ट लगा दी। फाबिया ने कई बार अनुरोध किया की रिपोर्ट तो सही लगाइए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद उसने 10 जून 2025 को स्वयं हुए मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप पुनः रि-मेडिकल मण्डलीय चिकित्सा परिषद से कराए जाने का अनुरोध किया। तत्कालीन सीएमओ डॉ. श्रीकांत शुक्ला ने पुनः जांच के लिए निर्दे?शित किया। मण्डलीय चिकित्सा परिषद, गोरखपुर मंडल गोरखपुर की ओर से मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच कराई गई तो सच्चाई सामने आ गई। एक जुलाई 2025 को फाबिया मण्डलीय चिकित्सा बोर्ड के सामने पेश हुई। प्रपत्रों एवं फाबिया का परीक्षण किया गया। 23 सितंबर 2025 की रिपोर्ट में हकीकत सामने आ गई। छोटी उंगली के मध्य पोर के शीर्ष का रेखीय विस्थापित फैक्चर रिपोर्ट में दर्शाया गया है। पीड़िता ने बताया कि मेडिकल बोर्ड की जांच सही तथ्य सामने आ गया। अगर इतनी जद्दोजहद नहीं हुई होती तो यह रिपोर्ट सही नहीं मिलती। उनका आरोप है कि जिला अस्पताल में कोई रिपोर्ट बनवानी हो तो रकम दिए बगैर सही नहीं बनेगी। गलत को सही बनाना और सही को गलत बना देना कोई नई बात नहीं है। ऐसा यहां अक्सर होता है, लेकिन भ्रष्टाचार के ?खिलाफ कम ही लोग मुखकर होकर आगे बढ़ते हैं। मामले में पीड़िता के अ??धिवक्ता सोमनाथ चौरसिया कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड से हड्डी फैक्चर होने की रिपोर्ट मिलने के बाद मारपीट की धारा में बढ़ोतरी कराई जाएगी। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। इस तरह की अंधेरगर्दी करने वालों जिम्मेदारों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। कोठीभार थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

3 जून 2025 को हुई मारपीट की घटना में फाबिया की टूटी उंगली की जांच में डॉक्टरों ने नो बोन फैक्चर की रिपोर्ट लगा दी

नेपाल बार्डर पर नशे का धंधा तेज, 11 ग्राम हेरोइन बरामद

महराजगंज। भारत नेपाल सीमा पर नशे का धंधा तेज हो गया है। कभी नशे में प्रयोग होने वाली दवा तो कभी हेरोइन व चरस की बरामदगी होती रहती है। आठ अप्रैल की देर रात शिवा यादव निवासी लक्ष्मीनगर टोला बैकुंठपुर को नेपाल बार्डर पर 11 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर चालान कर दिया। न्यायालय ने आरोपी को 9 अप्रैल को जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, भारत नेपाल सीमा पर अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के लिए सख्ती बरती जा रही है। उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में थाना सोनौली पुलिस आठ अप्रैल की देर रात्रि भ्रमण के दौरान आरोपी को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। युवक से पूछताछ में कुछ अहम जानकारी जुटाई गई है। इस पर पुलिस टीम जांच कर रही है। बार्डर क्षेत्र में युवक इस तरह के धंधे में लिप्त हैं। ज्यादातर वे ही गिरफ्तार होते हैं। माना जा रहा है कि कम समय में जल्दी अमीर बनने की लालच में युवक ऐसे धंधे में फंस जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि बार्डर क्षेत्र के हरदीडाली, भगवानपुर, बरगदवा, टूटीबारी, लक्ष्मीपुर, झुलनीपुर समेत अन्य क्षेत्रों से यह धंधा तेजी से हो रहा है। बीते दिनों नशे में प्रयोग के लिए दवाओं की खेप बरामद हुई थी। इसे लेकर बार्डर क्षेत्र में धंधेबाजों में हड़कंप मच गया है। इधर हेरोइन भी बरामद हो गई। नेपाल के काठमांडे, बुटवल समेत अन्य शहरों से तस्करों के नेटवर्क जुटे हैं। सूत्रों की मानें तो इनका नेटवर्क इतना मजबूत है की कभी कभार ही गिरफ्त में आते हैं। नौतनवा क्षेत्राधिकारी अनिरूद्ध कुमार ने बताया की आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी की जा रही है।

ओखला लैंडफिल का काला सच- राजधानी के जहरीले पहाड़ पर रोजगार की कीमत बनी बीमारी, मजदूरों पर चौंकाने वाला शोध

नई दिल्ली ।दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में स्थित ओखला लैंडफिल साइट पर काम करने वाले मजदूरों की हालत बेहद चिंताजनक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की शोधकर्ता मोनम एंगमो और इग्नू की प्रोफेसर शानी शाह के विस्तृत अध्ययन में यह बात साफ हुई है। पर्यावरण संरक्षण जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में खुलासा हुआ है कि यहां 55 से 60 लाख टन पुराना कचरा (लेगेसी वेस्ट) अभी पड़ा है। यह साइट 1996 से चालू है और 2010 में भर चुकी थी, फिर भी कचरा डालना जारी रहा। ऐसे में यहां काम करने वाले मजदूरों के लिए यह जहरीला पहाड़ बन गया है। करीब 36 मजदूरों को स्किन एलर्जी, 32 को सांस की बीमारी, 23 को आंखों में लालिमा या बाल झड़ने की समस्या और 8.5व को दिल से जुड़ी दिक्कतें हैं। अध्ययन के अनुसार, इनमें से 76 प्रतिशत मजदूर अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। शोध में 107 मजदूरों से सीधे सवाल-जवाब किए गए, जिनमें ज्यादातर पुरुष थे और उनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच थी। नतीजे देखकर हैरानी होती है। 95 प्रतिशत मजदूरों को पता है कि रोजाना कितना कचरा (लगभग 2000 टन) यहां आता है लेकिन क्या करें रोजी-रोटी के लिए काम करते हैं। मजदूर लैंडफिल की असली स्थिति से अनजान हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि लैंडफिल पर आरामघरों की हालत बेहद खराब है। 51 प्रतिशत मजदूरों ने बताया कि टॉयलेट और आराम की जगह गंदी, बिना पानी और अस्वच्छ है। लीचेट यानी कचरे से निकलने वाला जहरीला पानी का कोई प्रबंधन नहीं है। शोधकर्ता मोनम एंगमो के अनुसार, 2018 में लैंडफिल में आग लगी थी, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को भारी नुकसान हुआ। 2019 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पुराने कचरे को हटाने का आदेश दिया। एसडीएमसी ने बायो-माइनिंग शुरू की और छह ट्रॉमेल मशीनें लगाईं। 2024 तक साइट साफ करने का टारगेट था। कचरे में 52 प्रतिशत मिट्टी जैसा पदार्थ, 42 प्रतिशत ईंट-पत्थर-कंक्रीट और 5 प्रतिशत प्लास्टिक है। ऑर्गेनिक कंटेंट सिर्फ 6.3 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि एसडीएमसी ने वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट शुरू किया, जिससे लैंडफिल पर बोझ कम हुआ, लेकिन मजदूरों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया। शोध में बताया गया है कि कचरा मुख्य रूप से साउथ दिल्ली के चार जोन से आता है। 46 प्रतिशत कचरा एनर्जी प्लांट में जाता है, 3 प्रतिशत कंपोस्टिंग के लिए और बाकी सीधे लैंडफिल में। घरों में सेग्रिगेशन नहीं होने से समस्या बढ़ती है। रैग-पिकर्स अनौपचारिक रूप से कचरा अलग करते हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य कार्ड या सुविधाएं नहीं मिलतीं। शोधकर्ताओं ने सिफारिशें की हैं। इसमें एसडीएमसी को हर वार्ड में सेग्रिगेशन सेंटर बनाना चाहिए। रैग-पिकर्स को स्वास्थ्य कार्ड और सुविधाएं देनी चाहिए। मजदूरों को सालाना स्वास्थ्य जांच, अच्छी क्वालिटी का पीपीई और ट्रेनिंग देनी चाहिए।

आरामघर साफ-सुथरे बनाने चाहिए। लीचेट का प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। कचरा स्रोत पर अलग करने से लैंडफिल का बोझ कम होगा और ग्रीनहाउस गैसें भी घटेंगी। ओखला लैंडफिल ओखला बर्ड सैंक्चुअरी और अन्य इको-सेंसिटिव जोनों के पास है, इसलिए इसे जल्द साफ करना जरूरी है। कोरोना महामारी के दौरान भी मजदूरों ने बिना रुके काम किया। लॉकडाउन में कचरा कम हुआ, लेकिन 73 प्रतिशत मजदूर रोजाना आते रहे।

अब नहीं होगी एलपीजी की किल्लत! 15,400 टन रसोई गैस लेकर भारत पहुंचा जहाज

मुंबई । नवी मुंबई के समुद्री तट से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध के बीच रसोई गैस लेकर एक भारतीय जहाज सुरक्षित भारत पहुंच गया है।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 को जानकारी दी कि 15,400 टन एलपीजी लेकर आ रहा एक बड़ा जहाज सफलतापूर्वक नवी मुंबई पोर्ट पर पहुंच चुका है। यह उपलब्धि इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इस जहाज ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक Strait of Hormuz को पार किया, जहां फिलहाल Iran, United States और Israel के बीच तनाव चरम पर है। ग्रीन आशा नाम का यह भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। इसे पोर्ट के उस विशेष बर्थ पर लगाया गया है, जिसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मिलकर संचालित करते हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद यह पहला ऐसा जहाज है, जो इतने जोखिम भरे माहौल के बावजूद सीधे इस पोर्ट तक पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक, यह भारत की समुद्री क्षमता और रणनीतिक तैयारी का मजबूत संकेत है।

क्रू और कार्गो पूरी तरह सुरक्षित

इस मिशन की सबसे राहत भरी बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। साथ ही, 15,400 टन एलपीजी की खेप और जहाज को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। पोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, यह घटना दिखाती है कि भारत कठिन वैश्विक परिस्थितियों में भी जरूरी ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में सक्षम है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम कदम

नवा शेवा पोर्ट देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां से गैस और तेल की सप्लाई देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाई जाती है। ऐसे में इस जहाज का सुरक्षित पहुंचना न केवल सप्लाई चेन के लिए राहत है, बल्कि यह भरोसा भी देता है कि भारत भविष्य में भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रख पाएगा।

हल्दिया में गारंटी देने के बाद आसनसोल में गरजे पीएम, कहा- भर गया टीएमसी के पापों का घड़ा

आसनसोल (पश्चिम बंगाल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के आसनसोल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत देवी कल्याणेश्वरी और घाघर बुरी चंडी का आह्वान करके की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में अब सत्ता परिवर्तन निश्चित है, जिसे आसनसोल और पूरे बंगाल की जनता चाहती है। उन्होंने टीएमसी पर सिंडिकेट राज, कोयला और रेत माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया । पीएम मोदी ने दावा किया कि टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है और बदलाव के बाद बंगाल नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने बताया कि कभी समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र रहे आसनसोल से निवेश पलायन कर गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही इस स्थिति को सुधार सकती है। उन्होंने उल्लेख किया कि बंगाल का राज्य सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 12 फीसदी से घटकर केवल पांच फीसदी रह गया है।

विकास और केंद्र का योगदान

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने

आसनसोल में उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए 45,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने बंगाल को केवल निर्ममता दी है, जबकि भाजपा ने बाधाओं के बावजूद आसनसोल का विकास किया है। मोदी ने कहा कि आसनसोल और दुर्गापुर दोनों में महानगर बनने की क्षमता है। उन्होंने वादा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार यह विकास लाएगी।

भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया

पीएम मोदी ने दावा किया कि भाजपा ने भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया है और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा भी भाजपा ही सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा आपका एक वोट बंगाल के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी बनेगा। उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया कि एक समुदाय के नाम पर हिंदुओं को धमकाया जा रहा है और बंगाल में घुसपैठियों के बढ़ते दबदबे से लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। कुछ जगहों पर मंदिर जाने और पूजा करने पर पाबंदी लगी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सब टीएमसी सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने साफ कहा कि 4 मई के बाद बंगाल में कानून का असली राज चलेगा और हर तरह की गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। पीएम मोदी ने टीएमसी को बीरबलहट और जनता के भरोसे की बात करते हुए कहा कि बंगाल की जनता देशभक्त होगी और इस चुनाव में टीएमसी का कोई हथकंडा काम नहीं आएगा।

सीएपीएफ जवानों के सम्मान और हक के लिए राहुल गांधी का संकल्प, बोले- खत्म होगी नाइंसाफी

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, तो वह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों को नेतृत्व के अवसरों से वंचित करने वाली भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त कर देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें उनके उचित अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हों। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शौर्य दिवस के अवसर पर गांधी ने कहा कि वे और कांग्रेस पार्टी दोनों सीएपीएफ कर्मियों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने ही बलों के भीतर पदोन्नति के अवसर, शीर्ष नेतृत्व पदों तक पहुंच और उचित सम्मान उनके उचित अधिकार हैं। गांधी ने हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि सीआरपीएफ वीरता दिवस के अवसर पर, मैं हमारे बल के साहसी और वीर सैनिकों को हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विपक्ष के नेता ने कहा कि आपका साहस और बलिदान प्रतिदिन हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं।

सीमाओं पर तैनात रहकर आप देश को सुरक्षित रखते हैं, आप आतंकवाद और नक्सलवाद के खतरों का सामना करते हैं और आप यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार - हमारे चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि हालांकि, सच्ची श्रद्धांजलि केवल शब्दों से नहीं दी जा सकती। वर्षों के बलिदान, कठिन कर्तव्य और सेवा के बावजूद, सीएपीएफ कर्मियों को न तो समय पर पदोन्नति मिलती है और न ही उन्हें अपनी फोर्स का नेतृत्व करने का अधिकार, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व पद संगठन के बाहर के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। गांधी ने आगे कहा कि सीएपीएफ कर्मियों के पास विशेष प्रशिक्षण, मूल्यवान जमीनी अनुभव और गहरी रणनीतिक समझ है। गांधी ने तर्क दिया कि इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अनिवार्य है कि इन बलों का नेतृत्व उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाए जो स्वयं इसी व्यवस्था से आते हैं और सैनिकों की अनूठी चुनौतियों और आवश्यकताओं को सही मायने में समझते हों। उन्होंने कहा कि नेतृत्व के अवसरों से वंचित किए जाने से लेकर वेतन, कल्याण और सम्मान से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों का सामना करने तक, यह संस्थागत अन्याय उन सैनिकों के मनोबल को कमजोर करता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है।

अखिलेश ने सरकार पर कसा तंज, कहा- भाजपाइयों के लिए एआई का मतलब इनकम

लखनऊ । समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार जाते-जाते हर तरीके से जनता से पैसे वसूलने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से वसूली कराई जा रही थी और अब एआई के नाम पर जनता को लूटने का नया तरीका निकाला गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपाइयों के लिए एआई का मतलब आमदनी (इनकम) बन गया है। यादव ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, ट्रैफिक जाम के पीछे कई वास्तविक कारण हैं, जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसकी वजह सड़कों की खराब स्थिति, संकरी सड़कें, खराब ट्रैफिक सिग्नल, नाकाबंदी, रूट डायवर्जन, वन-वे व्यवस्था की कमी, जलभराव, डिवाइडर की खराब हालत और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन आदि हैं। ट्रैफिक पुलिस की कार्य परिस्थितियां भी बेहद खराब हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। ड्राइवरों पर समय पर पहुंचने का दबाव, मानसिक तनाव और वाहनों की खराब फिटनेस भी दुर्घटनाओं और जाम की वजह बन रही है।सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चौराहों पर ट्रैफिक

*** उन्होंने कहा कि पहले ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से वसूली कराई जा रही थी और अब एआई के नाम पर जनता को लूटने का नया तरीका निकाला गया है।**

पुलिस की मौजूदगी कम रहती है, जबकि आगे मोड़ों पर छिपकर चालान काटने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अब डिजिटल पेमेंट के जरिए वसूली का नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर रिकॉर्डिंग केवल चुनिंदा मामलों में ही उपलब्ध कराई जाती है, जबकि अन्य मामलों में तकनीकी खराबी का हवाला दिया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता अब इस व्यवस्था से परेशान हो चुकी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए तैयार है।

गैस रिसाव के बाद क्वार्टर में लगी आग, 7 बच्चों समेत 11 लोग झुलसे

यमुनानगर ।

हरियाणा के यमुनानगर जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बृहस्पतिवार सुबह सलेमपुर बांगर इलाके में प्रवासी मजदूरों के एक आवासीय क्वार्टर में एलपीजी सिलेंडर फटने से 7 बच्चों समेत कुल 11 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतना जोरदार था कि क्वार्टर की दीवारें तक ढह गईं।

जगाधरी (सदर) थाना प्रभारी तरसेम कुमार के अनुसार, यह घटना एक स्थानीय कारखाने के पास बने लेबर क्वार्टर में हुई। सुबह के समय एक परिवार लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहा था। इसी दौरान पास में रखे एक गैस सिलेंडर से रिसाव शुरू हो गया। चूल्हे की चिंगारी ने लीक हो रही गैस को पकड़ लिया, जिससे आग लग गई।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हो गया। विस्फोट के प्रभाव से कमरे की दीवारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने बताया, पास में रखे एक सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ और इसमें आग लग गई। देखते ही

देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और फिर इसमें धमाका हुआ, जिससे क्वार्टर की दीवारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

अधिकारियों ने बताया कि घायलों में दो महीने का एक शिशु, 43 वर्ष के दो पुरुष, एक महिला (40) और 18 वर्षीय युवती शामिल है जबकि अन्य घायल बच्चों की उम्र पांच से 10 वर्ष के बीच बताई गई है। उन्होंने बताया, घटना के बाद घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से झुलसे आठ लोगों को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच जारी है।

मणिपुर में बम हमले के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर उतरे हजारों लोग

इंफाल। मणिपुर के घाटी क्षेत्रों के पांच जिलों में कर्फ्यू को दरकिनार करते हुए हजारों लोगों ने बम हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर विरोध जताया और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इस हमले में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इंफाल पश्चिम जिले के टिड्डिम लाइन में ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गनाइजेशन के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि सुरक्षा बलों ने रैली को क्वाकेइथेल के पास आगे बढ़ने से रोक दिया। बाद में संगठन के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से मिलने ले जाया गया।

शांतिपूर्ण मतदान के साथ असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव संपन्न, अब फैसले का इंतज़ार

नेशनल डेस्क । असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। असम की 126 सीटों, केरलम की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न हो गया है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है।

असम विधानसभा चुनाव में शाम पांच बजे तक 86.92 प्रतिशत मतदान

असम विधानसभा चुनाव में शाम पांच बजे तक 86.92 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। राज्य की सभी 126 सीटों के लिए मतदान आज सुबह सात बजे शुरू हुआ था और आयोग ने मतदान समाप्ति का समय शाम पांच बजे तक तय किया था लेकिन यह समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कई लोग मतदान के लिए कतार में लगे हुये थे। चुनाव आयोग के अनुसार पांच बजे तक 86.92 प्रतिशत मतदान हुआ है। राज्य में इक्का दुक्का घटना के अलावा कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

94.08 प्रतिशत और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में हुआ मतदान

चुनावी राज्य के दक्षिण सलमारा मनकाचार जिले में सबसे अधिक 94.08 प्रतिशत और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में सबसे कम 72.94 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके अलावा बजाली जिले में 86.89 प्रतिशत, बक्सा में 82.51, बारपेटा में 91.92, बिश्वनाथ में 83.76, बोंगाईगांव में 91.77, कछार में 82.19, चराईदेव 82.91, चिरांग में 86.06, दरंग में 90.91, धेमाजी में 79.04, धुबरी में 90.63, डिब्रूगढ़ में 80.02, दीमा हसाओ में 79.96,

गोलपारा में 91.34, गोलाघाट में 80.96, हैलाकांडी में 78.90, होजाई में 87.13, जोरहाट में 79.93, कामरूप (मेट्रो) में 76.41, कामरूप (ग्रामीण) में 86.87, कार्बी आंगलोंग में 75.42, कोकराझार में में 86.59, लखीमपुर में 84.41, माजुली में 83.67, मोरीगांव में 88.95, नगांव में 87.18, नलबाड़ी में 86.89, शिवसागर में 83.30, सोनितपुर में 82.23, श्रीभूमि में 83.35, तमुलपुर में 82.00, तिनसुकिया 78.85, और उदलगुरी में 82.29 प्रतिशत मतदान हुआ। असम के कामरूप जिले में मतदान समाप्त होने पर मतदान अधिकारियों ने ईवीएम और वीवीपैट को सील किया।

पीठासीन अधिकारी ने लोगों को दिया धन्यवाद

एक पीठासीन अधिकारी ने कहा, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, मैं चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं।%असम विधानसभा चुनाव 2026 के बीच उदलगुड़ी सीट से उम्मीदवार मुरेन दैमरी को लेकर विवाद बढ़ गया है। पार्टी के एक नेता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए प्राथमिकी की मांग की है। आरोप है कि श्री दैमरी ने पार्टी के खिलाफ बयान दिए।

असम में 722 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद

राज्य में बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। असम की सभी 126 सीटों के लिए कुल 722 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। राज्य में 2.50 से अधिक मतदाताओं के लिए कुल 28,205 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। कुल मतदाताओं में 1.25 करोड़ पुरुष, 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं और 343 उभयलिंगी मतदाता शामिल हैं। मतगणना चार मई को होगी और उसी दिन परिणाम आ जायेंगे।

शाम पांच बजे तक 75.01 प्रतिशत मतदान

केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए मतदान बृहस्पतिवार शाम छह बजे समाप्त हो गया, लेकिन कई मतदान केंद्रों के बाहर अब भी लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। शाम छह बजे मतदान केंद्रों पर मौजूद लोगों को टोकन दिए गए और उन्हें वोट डालने की अनुमति दी गई। शाम पांच बजे तक 75.01 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो 2021 के विधानसभा चुनावों के 74.06 प्रतिशत मतदान से थोड़ा अधिक है। अंतिम मतदान प्रतिशत तभी उपलब्ध होगा जब मतदान केंद्रों पर बचे सभी लोग अपना वोट डाल लेंगे।

पुडुचेरी में शाम छह बजे तक करीब 86 प्रतिशत मतदान

पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान बृहस्पतिवार शाम छह बजे समाप्त हो गया। मतदान समाप्त होने की समय सीमा से पहले पहुंचे और कतार में खड़े लोगों को वोट डालने की अनुमति दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 86 प्रतिशत से अधिक लोगों ने मतदान किया। अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेस (एआईएनआरसी) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सत्ता बरकरार रखने के लिए और, विपक्षी कांग्रेस नीत गठबंधन केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव के लिए जोर लगा रहा है।

परमाणु मुद्दे पर अड़ा ईरान: ट्रंप को दो टूक संदेश- यूरेनियम संवर्धन से नहीं हटेंगे!

तेहरान । ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और इस बीच घोषित युद्धविराम अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ईरान की परमाणु एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि परमाणु कार्यक्रम के तहत यूरेनियम संवर्धन का अधिकार बचाए रखना अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए अनिवार्य शर्त है।

युद्धविराम पर मंडराते संकट के बादल

28 फरवरी से शुरू हुए इस भीषण युद्ध को रोकने के लिए जिस युद्धविराम की घोषणा की गई थी, वह फिलहाल लड़खड़ाता नजर आ रहा है। दरअसल, पाकिस्तान में नियुक्त ईरानी राजदूत रजा अमीरी मुगद्दम ने इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल के आगमन वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी है। यह पोस्ट हटाए जाने के बाद वार्ता के आयोजन पर संशय और सस्पेंस गहरा गया है, जिससे पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

इन वजहों से टल सकता है सीजफायर

हालांकि, सिर्फ यही कारण नहीं है। इससे पहले युद्धविराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इस्राइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जोरदार हमले किए। बुधवार का दिन इस युद्ध का सबसे खूनी दिन साबित हुआ। इस्राइली हमले में 250 से अधिक लोग मारे गए। ईरान का दावा है कि युद्धविराम में लेबनान भी शामिल था, जबकि इस्राइल और अमेरिका इससे इनकार कर रहे हैं। इसके इतर, दुनिया के 20 फीसदी तेल व्यापार के लिए अहम होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बरकरार है। लेबनान पर हुए हमले के बाद ईरान ने इसे फिर से बंद कर दिया है। ईरानी एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके गए तो होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। दूसरी ओर ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया, तो उसे पहले से भी कहीं अधिक घातक हमलों का सामना करना पड़ेगा।

*** ईरान बोला- अमेरिका ने सीजफायर की 3 शर्तें तोड़ीं, अब बातचीत बेकार**

***ट्रम्प बोले- समझौते तक ईरान के आसपास आर्मी तैनात रहेगी**

***इजराइली सेना ने बुधवार को लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक, इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1,165 लोग घायल हुए। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है।**

सऊदी और ईरानी विदेश मंत्री ने की फोन पर चर्चा

खबर है कि पाकिस्तान में होने वाली निर्णायक शांति वार्ता से ठीक पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। दोनों देशों के विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को घटाने और क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने के रास्तों पर गहन मंथन किया।

ऐसे समय में जब लेबनान पर इस्राइली हमलों और होर्मुज की घेराबंदी ने युद्धविराम को खतरे में डाल दिया है, ईरान का सऊदी अरब से संपर्क करना यह संकेत देता है कि वह वार्ता की मेज पर जाने से पहले क्षेत्रीय शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।